



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1935 (श0)
(सं0 पटना 529) पटना, बृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

11 अप्रैल 2013

सं0 22/नि0सि0(पट0)—03-02/2010/432—श्री ज्योति प्रकाश सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, बिहारशरीफ सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल-2, गोपालगंज के विरुद्ध जल पथ प्रमण्डल, बिहारशरीफ में कार्यरत अवधि में निम्नलिखित प्रथम द्रष्टया आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापक 1054 दिनांक 18.8.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किया गया:-

आरोप-1— प्रथम चरण के कुल 21 जमींदारी बांधों में से शेष 7 बचे जमींदारी बांधों में से कुल दो अदद जमींदारी बांधों के पूर्ण होने की तिथि 16.12.09 थी। उक्त दो अदद जमींदारी बांधों के निर्माण में संवेदकों द्वारा कोताही बरतने पर भी उनके द्वारा मात्र उच्चाधिकारियों से पत्राचार की महज कागजी खानापूर्ति किया गया जबकि उनको एकरारनामा के शर्तों के आलोक में दण्डात्मक कार्रवाई करना चाहिये था।

उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वयं स्वीकार किया गया है कि प्रथम चरण के कुंभरी नदी एवं जिराईन नदी के दोनों जमींदारी बांधों के मिट्टी कार्य का क्रमशः 93 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत कार्य कराया गया परन्तु कुंभरी नदी के जमींदारी बांधों से संबंधित 40 अदद संरचना में से मात्र 6 अदद संरचना का ही कार्य कराया गया था जो उनकी कार्यों के प्रति अभिरुची में कमी एवं उदासीनता को दर्शाता है तथा लगाया गया उपर्युक्त आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित होता है।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री ज्योति प्रकाश सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को कार्यों के प्रति अभिरुची में कमी और उदासीनता का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया किन्तु संवेदक के विरुद्ध जमींदारी बांध के निर्माण में कोताही बरतने एवं निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर भी एकरारनामा के शर्तों के आलोक में दण्डात्मक कार्रवाई नहीं किये जाने का आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

उक्त आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-1026 दिनांक 20.9.12 द्वारा श्री सिंह को निम्नदण्ड संसूचित किया गया:-

1. निन्दन वर्ष 2009-10

2. दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त संसूचित दण्ड के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा पुनर्विलोकन/ पुनर्विचार अर्जी समर्पित किया गया जिसमें मुख्य रूप से निम्न तथ्य दिये गये हैं:-

श्री सिंह द्वारा कहा गया है कि जांच पदाधिकारी द्वारा विभाग में समर्पित जांच प्रतिवेदन की प्रति दण्ड संसूचन के पूर्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(3) के तहत उपलब्ध नहीं करायी गयी है फलतः विभाग के समक्ष पक्ष रखने से वंचित हो गया जो नियमावली 2005 के नियम 18 (3),(4) एवं माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेकों न्यायादेशों में दिये गये स्पष्ट निदेश एवं नैसर्गिक न्याय के अनुरूप नहीं है। परन्तु साक्ष्य के रूप में कागजात संलग्न नहीं किया गया है।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1054 दिनांक 18.8.11 के माध्यम से निदेशित विभागीय कार्यवाही में गठित एक आरोप के दो अंश हैं। आरोप के प्रथम अंश के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने समीक्षा में दोषमुक्त माना गया है तथा यह भी अंकित किया गया है कि निरन्तर पत्राचार एवं प्रतिमाह प्रगति प्रतिवेदन समर्पण के बावजूद अधीक्षण अभियन्ता से दण्डात्मक कार्रवाई हेतु कोई निदेश नहीं दिया गया था जो एस0 बी0 डी0 एकरारनामा के क्लॉज-2 के अनुसार सक्षम प्राधिकार है।

मुख्य अभियन्ता, पटना द्वारा कुंभरी नदी तथा जिराईन नदी के तटबंधों के कार्य के लिये संवेदक को लिखा गया परन्तु उक्त पत्र की प्रति जो कार्यपालक अभियन्ता को दी गई उसमें एकरारनामा को विखंडित करने/ दण्डात्मक कार्रवाई करने का आदेश नहीं था। साक्ष्य के रूप में उक्त पत्र की प्रति दी गई है। उक्त पत्र की प्रति संचालन पदाधिकारी के समक्ष बचाव बयान के साथ भी समर्पित किया था परन्तु उसे नजर अंदाज करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप के प्रथम अंश के लिए आंशिक रूप से दोषी मानने की विसंगति की गयी है।

विभागीय अधिसूचना सं0-1026 दिनांक 20.9.12 द्वारा संसूचित दण्ड (1) निन्दन वर्ष 2009-10 (2) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक, लघु दण्ड के अन्तर्गत आते हैं परन्तु उक्त दण्ड के फलस्वरूप मेरी प्रोन्नति पाँच वर्षों तक बाधित हो जाती है जो वृहद दण्ड के समरूप हो जाता है।

श्री सिंह द्वारा कहा गया है कि नियमावली 2005 के नियम 27 (2),(क) के आलोक में नियमावली 2005 के नियम 18 (3),(4) का अनुपालन नहीं किया गया है तथा नियमावली 2005 के नियम 27 (2),(ख) के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्गत दण्ड साक्ष्य द्वारा समर्पित नहीं है।

श्री सिंह से प्राप्त पुनर्विलोकन/पुनर्विचार अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री ज्योति प्रकाश सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता का यह कथन कि दण्ड संसूचन के पूर्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(3) के तहत संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे अपना पक्ष रखने से वंचित हो गया, संसूचित दण्ड के परिपेक्ष्य में लागू नहीं होता, क्योंकि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(6) में यह प्रावधान है कि नियम 14 के खंड (6) से (10) में विनिर्दिष्ट शस्तियों में से कोई सरकारी सेवक पर अधिरोपित करने के लिये अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

एस0 बी0 डी0 एकरारनामा के क्लॉज-2 के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता दण्डात्मक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार है। श्री सिंह, कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कार्य एवं संवेदक के संबंध में हमेशा पत्राचार किया गया है एवं कार्य का प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाता रहा है परन्तु मुख्य अभियन्ता, पटना द्वारा संवेदक को लिखे गये पत्रों जो श्री सिंह के द्वारा ही साक्ष्य के रूप में समर्पित किया गया है, में संवेदक को दिये गये निदेश कि "कार्य एक सप्ताह के अन्दर प्रारम्भ कर समाप्त करें अन्यथा बाध्य होकर एकरारनामा में निहित शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ठीकेदार निबंधन नियमावली के तहत कार्रवाई हेतु संसूचित कर दिया जायेगा" को प्रतिलिपि प्राप्ति के बावजूद भी दिये गये निदेश के आलोक में संवेदक द्वारा कार्यपूर्ण नहीं करने की स्थिति में संवेदक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों को ठोस प्रस्ताव नहीं दिया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन की समीक्षा में दिये गये तथ्य कि "श्री ज्योति प्रकाश सिंह, कार्यपालक अभियन्ता पर कार्यों के प्रति अभिरुचि में कमी और उदासीनता के आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं" जबकि संवेदक के एकरारित अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप एस0 बी0 डी0 की धारा के आलोक में दण्डात्मक कार्रवाई स्वयं नहीं करने/ दण्डात्मक कार्रवाई का स्पष्ट प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता को समर्पित नहीं किये जाने का यद्यपि आरोप प्रमाणित होता है। प्राप्त जांच प्रतिवेदन की विस्तृत समीक्षोपरान्त ही श्री सिंह को आंशिक रूप से दोषी मानते हुए लघु दण्ड के श्रेणी में आने वाले शास्ति को विभागीय अधिसूचना सं0-1026 दिनांक 20.9.12 से निर्गत किया गया है। श्री सिंह द्वारा पुनर्विलोकन/ पुनर्विचार अर्जी में भी स्वीकार किया गया है कि निर्गत दण्ड लघु दण्ड के श्रेणी में आते हैं।

श्री सिंह के विरुद्ध संसूचित दण्ड समर्पित साक्ष्य के अनुकूल है क्योंकि संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में इन्हें आंशिक रूप से दोषी माना गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सिंह द्वारा दिये गये पुनर्विलोकन/पुनर्विचार अर्जी के समीक्षोपरान्त पाया गया कि अर्जी में दिये गये कोई भी तथ्य विचारणीय विन्दु के अन्तर्गत नहीं आते हैं। अतः उक्त पुनर्विलोकन/पुनर्विचार अर्जी को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

अतएव श्री ज्योति प्रकाश सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता से प्राप्त पुनर्विलोकन/पुनर्विचार अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

एतद् द्वारा उक्त निर्णय श्री सिंह को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

श्याम कुमार सिंह,

सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 529-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>